राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)
54वाँ प्रांतीय अधिवेशन, श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय, सीकर

दिनांक 31 जनवरी 2015 व 1 जनवरी 2016

महामंत्री प्रतिवेदन

संगठन का 53 वाँ प्रदेश अधिवेशन 18 व 19 फरवरी 2015 को श्री गोविन्द गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में सम्पन्न हुआ। 53वें अधिवेशन एवं उसके पश्चात् शिक्षक समस्याओं के समाधान हेतु संगठन द्वारा किए गए प्रयासों एवं उपलब्धियों के साथ सम्पन्न सांगठनिक एवं वैचारिक कार्यक्रमों का विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत है-

शिक्षक समस्याओं के संबंध में उपलब्धियाँ एवं गतिविधियाँ

* **30 जून 2013 तक पात्र शिक्षकों के पे-बैंड-4 के आदेश जारी** - गत वर्ष नवम्बर माह में आयोजित वरिष्ठ व चयनित वेतनमान की स्क्रीनिंग के समय से ही संगठन ने अनेक बार उच्च शिक्षा मंत्रीजी एवं विभाग के अधिकारियों से भेंट कर एवं पत्र लिख कर 30 जून 2010 तक चयनित वेतनमान में पदोन्नत महाविद्यालय शिक्षकों को बिना ए.पी.आई. अंक व किसी संवीक्षा प्रक्रिया के पे-बैंड-4 का लाभ प्राचार्य स्तर पर स्वीकृत करने की लगातार मांग की। संगठन के लगातार प्रयासों व दबाव की सकारात्मक परिणिति के रूप में 30 जून 2010 तक चयनित वेतनमान में पदोन्नत महाविद्यालय शिक्षकों को उनके द्वारा चयनित वेतनमान में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर बिना किसी ए.पी.आई. अंक की आवश्यकता के प्राचार्य स्तर पर ही पे-बैंड-4 देने के आदेश दिनांक 10-11-2015 को जारी हो गए।
* **वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान स्वीकृति पर 3 प्रतिशत वेतन वृद्धि के आदेश** - राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा दिनांक 12-10-2009 को जारी छठे वेतनमान के आदेशों में सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान स्वीकृति के समय 3 प्रतिशत की एक वेतनवृद्धि का प्रावधान होने के बावजूद अनेक महाविद्यालयों में शिक्षकों को उक्त लाभ नहीं दिया जा रहा था। संगठन के निरन्तर प्रयासों से इस संदर्भ में दिनांक 22-4-2015 को स्पष्टीकरण आदेश जारी किये गए।
* **वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान की एरियर राशि के नगद भुगतान के आदेश** - गत 10-12-2014 को आयुक्तालय द्वारा 189 शिक्षकों को वरिष्ठ एवं 356 शिक्षकों को चयनित वेतनमान स्वीकृत किए थे। अनेक महाविद्यालयों में एरियर राशि के नगद भुगतान को लेकर संशय होने पर संगठन के प्रयासों से आयुक्तालय द्वारा दिनांक 26 मार्च 2015 को एरियर के नगद भुगतान के आदेश प्रसारित किए गए।
* **परिवीक्षा काल में कार्यरत व्याख्याताओं का मानदेय संशोधित** - मुख्यमंत्रीजी द्वारा राज्य सेवा में परिवीक्षा काल में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा का लाभ महाविद्यालय शिक्षकों पर लागू करने के लिए संगठन द्वारा दबाव बनाया गया। संगठन के प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा दिनांक 2 जुलाई 2015 को परिवीक्षाकाल में कार्यरत महाविद्यालयों शिक्षकों, पुस्तकालाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षकों का नियत मानदेय 1 सितम्बर 2014 से 21840 एवं 1 जुलाई 2015 से 24030 रुपये करने के आदेश प्रसारित किये गए।
* **परीक्षा पारिश्रमिक वृद्धि** - विश्वविद्यालय परीक्षा पारिश्रमिक वृद्धि के लिए संगठन के निरन्तर दबाव की परिणिति में गत सत्र 2014-15 से अनेक विश्वविद्यालयों में परीक्षा संबंधी सभी कार्यों के लिए देय पारिश्रमिक दरों में वृद्धि की गई। कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा पारिश्रमिक नहीं बढ़ाया गया था अथवा वृद्धि समान नहीं थी। इस संदर्भ में संगठन ने राज्यपाल महोदय एवं संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपति से पारिश्रमिक में एकरूपता लाने का आग्रह किया। संगठन के प्रयासों से अधिकांश विश्वविद्यालयों के परीक्षा पारिश्रमिक संशोधित हो चुके हैं। कुछ विश्वविद्यालयों के परीक्षा पारिश्रमिक दरों में विसंगतियों के निवारण की कार्यवाही चल रही है।

* **जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की संवैधानिक कमेटियों में सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अध्यादेश संशोधन हेतु कमेटी गठित** - जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, जो पूर्व में परिसर विश्वविद्यालय था, को संभागीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद अन्य विश्वविद्यालयों की भांति सिंडीकेट, सीनेट एवं अन्य कमेटियों में संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व देने हेतु संगठन ने लगातार दबाव बनाया। संगठन के लगातार प्रयासों से जोधपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने सम्बद्ध महाविद्यालय शिक्षकों को वैधानिक समितियों में प्रतिनिधित्व देने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है।
* **1-1-2006 से पूर्व सेवानिवृत्त कॉलेज शिक्षकों, पुस्तकालाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षकों की पेंशन संशोधन** - 1-1-2006 से पूर्व सेवानिवृत्त ऐसे कॉलेज शिक्षकों, पुस्तकालाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षकों जिन्होंने सेवानिवृत्ति पूर्व चयनित वेतनमान में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी उनका पेंशन नियतन पे-बैंड 4 व ए. जी.पी. 9000 के अनुसार करने की मांग संगठन राज्य सरकार से लगातार करता आया है। राज्य सरकार द्वारा प्रकरण में सकारात्मक रूख नहीं रखने के कारण सेवानिवृत्त शिक्षक साथियों को माननीय उच्चतम न्यायालय में इस मामले को ले जाना पड़ा। अन्ततः उच्चतम न्यायालय ने न्याय प्रदान करते हुए प्रार्थी शिक्षकों की पेंशन संशोधित करने का निर्णय दिया गया है। संगठन ने पुनः राज्य सरकार से अपील की है कि इस संबंध में प्रार्थी शिक्षकों के समान ही पात्र सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन को भी संशोधित किया जाय।
* **महाविद्यालयों में सेवानिवृत्त व्याख्याताओं एवं कार्मिकों की सेवाएं संविदा पर प्रारम्भ** - प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों को निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए लोक सेवा आयोग से नियमित चयन होने तक संगठन ने रिक्त पदों को अस्थाई तौर पर सेवानिवृत्त व्याख्याताओं एवं कार्मिकों से भरने की मांग की थी। संगठन की मांग के अनुरूप आयुक्तालय ने सेवानिवृत्त व्याख्याताओं एवं कार्मिकों को रिक्त पदों पर संविदा पर रखने की प्रक्रिया प्रारम्भ की। इसी श्रृंखला में आयुक्तालय ने आवेदनों के आधार पर 64 सेवानिवृत्त व्याख्याताओं, 32 मंत्रालयिक कर्मचारियों, 27 प्रयोगशाला सहायकों एवं 13 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संविदा पर नियुक्ति के आदेश प्रसारित कर दिए।
* **व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु कार्यवाही** - प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए संगठन के निरन्तर प्रयासों के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 1070 पदों की भर्ती हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। इन पदों की अभ्यर्थना भेजने के बाद राजकीय महाविद्यालयों में सेवानिवृत्ति एवं अन्य कारणों से कई और पद रिक्त हो गए थे। संगठन द्वारा सरकार के ध्यान में यह विषय लाया गया एवं इन रिक्त पदों पर भी भर्ती की मांग की गई। संगठन की मांग के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सत्र 2014-15 तक खाली हुए अन्य 220 पदों पर भर्ती हेतु लोकसेवा आयोग को अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है एवं लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।
* **मंत्रायलिक कर्मचारियों की भर्ती हेतु कार्यवाही** - प्रदेश के महाविद्यालयों में मंत्रायलिक कर्मचारियों की कमी के चलते महाविद्यालयों में प्रशासनिक एवं सामान्य काम-काज पर विपरीत प्रभाव पड़ता रहा है। संगठन लगातार इस विषय को पत्रों द्वारा तथा व्यक्तिगत भेंटवार्ताओं में उठाता रहा है। संगठन के इन निरन्तर प्रयासों के कारण महाविद्यालय शिक्षा के लिए लिपिक ग्रेड II (कनिष्ठ लिपिक) के 192 पदों की अभ्यर्थना राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रायलिक सेवा चयन बोर्ड को भिजवाई गई है। शीघ्र ही इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ होने की संभावना है।
* **प्राचार्य/उपाचार्य पद की डी.पी.सी. कार्यवाही प्रारम्भ** - संगठन लगातार प्रयासरत रहा है कि शिक्षकों को पदोन्नति लाभ समय पर प्राप्त हो एवं जिन महाविद्यालयों में प्राचार्य/उपाचार्य पद रिक्त है, उन महाविद्यालयों के सुचारू संचालन हेतु शीघ्र प्राचार्यों/उपाचार्यों की नियुक्ति की जाए। इस संबंध में संगठन ने प्राचार्य/उपाचार्य पद की डी.पी.सी. शीघ्र करवाने की मांग लगातार पत्रों एवं भेंटवार्ताओं में की थी। संगठन के दबाव के चलते उच्च शिक्षा विभाग ने आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है, संगठन को आशा है कि शीघ्र ही प्राचार्य/उपाचार्य पद पर डी.पी.सी. पूर्ण कर रिक्त पदों पर पदस्थापन कर दिया जाएगा।

❋ **प्राचार्य सम्मेलन में प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा) द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की निंदा** – 3 अगस्त 2015 को जयपुर में राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों के सम्मेलन में प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा श्री पवन कुमार गोयल ने प्राचार्यों पर बेबुनियाद आरोप लगाते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार किया। संगठन के संज्ञान में आते ही 4 अगस्त 2015 को उच्च शिक्षा मंत्रीजी को पत्र लिख कर एवं 7 अगस्त को व्यक्तिशः मिलकर प्राचार्य सम्मेलन में श्री गोयल के निरकुंश एवं गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की निंदा की गई तथा शिक्षकों की भावनाओं को उनके समक्ष रखते हुए श्री गोयल को भविष्य में संयमित व्यवहार रखने के निर्देश देने का आग्रह किया। उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से सुनकर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने के निर्देश दिये।

❋ **भेंट वार्ताएं** – शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के तीव्र एवं न्यायोचित समाधान करवाने हेतु संगठन ने समय-समय पर राज्यपाल महोदय, उच्च शिक्षा मंत्रीजी एवं विभाग के अधिकारियों से भेंट की।

❑ **राज्यपाल महोदय से भेंट** – संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने 11 मई एवं 6 अक्टूबर को राज्यपाल महोदय से भेंट कर पदनाम परिवर्तन में वित्त विभाग द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निस्तारण एवं विश्वविद्यालयों से संबंधित विभिन्न समस्याओं के निराकरण का आग्रह किया। संगठन द्वारा यू.जी.सी. रेग्यूलेशन, सूचना के अधिकार में प्राप्त राज्य सरकार द्वारा यू.जी.सी. को भेजी गई जानकारियों, एम.एच.आर.डी. के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों तथा 20 से अधिक राज्य सरकारों द्वारा जारी कॉलेज शिक्षकों के पदनाम परिवर्तन संबंधी आदेशों को संलग्न करते हुए राज्यपाल महोदय के समक्ष 400 से अधिक पृष्ठों का विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल महोदय से विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करवाने की प्रक्रिया प्रारंभ करवाने की मांग भी की। संगठन द्वारा सभी विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देने के लिए संबद्व महाविद्यालयों में कार्यरत पात्र शिक्षकों को पीएच.डी. सुपरवाईजर बनाने सहित शोध संबधी विभिन्न समस्याओं के निवारण करने, सेवारत महाविद्यालय शिक्षकों को पीएच.डी. हेतु कोर्स वर्क में छूट देने, जोधपुर विश्वविद्यालय की सिंडिकेट व अन्य कमेटियों में संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों को प्रतिनिधित्व देने एवं सभी विश्वविद्यालयों के परीक्षा पारिश्रमिक में एकरूपता लाने का भी आग्रह किया। राज्यपाल महोदय ने संगठन के पक्ष को विस्तार से सुना एवं आवश्यक निर्देश दिए।

❑ **उच्च शिक्षामंत्रीजी से भेंट** – संगठन शिक्षक समस्याओं के निराकरण के लिए उच्च शिक्षामंत्रीजी से लगातार सम्पर्क में रहा। संगठन द्वारा 7 अप्रेल, 11 मई, 7 अगस्त, 6 सितम्बर, 6 अक्टूबर, 25 नवम्बर एवं 19 दिसम्बर 2015 को उच्च शिक्षामंत्रीजी से की गई भेंटों में विभिन्न शिक्षक समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए उनके समर्थन में विभिन्न तथ्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये गए। संगठन के दृष्टिकोण से सहमत होते हुए विभिन्न समस्याओं के समाधान के क्रम में मंत्रीजी द्वारा सकारात्मक निर्देश प्रदान किये गए।

संगठन द्वारा की गई भेंटों में पदनाम परिवर्तन करने, पीएच.डी. के दोहरे लाभ प्रकरण में वसूली निरस्त करने एवं पीएच.डी. प्रोत्साहन वेतन वृद्धियाँ प्रारम्भ करने, पूर्व सेवा का लाभ सभी पात्र शिक्षकों को देने, निदेशक पद पर वरिष्ठतम शिक्षक नियुक्त करने, संतोषजनक ए.सी.आर. के आधार पर चयनित वेतनमान देने, आर.वी.आर.ई.एस. शिक्षकों को सी.ए.एस. लाभ देने, सेवारत शिक्षकों को पीएच.डी. कोर्स वर्क से छूट देने अथवा छह माह के सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था करने, अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति 2-1-2006 से 30-6-2006 के मध्य वार्षिक वेतनवृद्धि वाले शिक्षकों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने, संविदा शिक्षकों को यू.जी.सी. द्वारा अनुशंसित न्यूनतम वेतन देने सहित अन्य लंबित समस्याओं को शिक्षक हित में हल करने की मांग की गई। इसके अतिरिक्त बड़े महाविद्यालयों को विखंडित करने के उपरांत अभी तक सुचारू व्यवस्था नहीं किये जाने पर मंत्रीजी का ध्यान दिलाया गया तथा मांग की गई कि विखंडित महाविद्यालयों को शीघ्र स्वंतत्र रूप से चलाने की समुचित व्यवस्थाएं की जाए अथवा इनका पुनः एकीकरण कर दिया जावे। मंत्रीजी ने संगठन को बताया कि इस संबंध में निर्णय ले लिया गया है एवं अन्तिम आदेश हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय को फाईल

भेज दी गई है। संगठन ने 30 जून 2013 के बाद के वरिष्ठ चयनित वेतनमान एवं पे-बैंड-4 के लिए शीघ्र स्क्रीनिंग करवाने, आर.वी.आर.ई.एस. में नियुक्त शिक्षकों को उनकी अनुदानित पद पर सेवा अवधि के छठे वेतनमान के एरियर हेतु अनुदान देने, पूर्व संचित उपार्जित अवकाश नकदीकरण हेतु अनुदान उपलब्ध करवाने अथवा व्यापकहित में उपार्जित अवकाश एवं मेडिकल अवकाश को राज्य सेवा में अग्रनीत करने हेतु भी भेंटवार्ताओं में दबाव बनाया है।

❑ **अधिकारियों से भेंट** - पदनाम परिवर्तन से संबंधित 400 से अधिक पृष्ठों का विस्तृत ज्ञापन संयुक्त सचिव (सी.एम.ओ.) को 11 मई को दिया गया। 11 मई एवं 6 सितम्बर को उच्च शिक्षा से जुड़े अधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठकों में विभिन्न शिक्षक समस्याओं के निराकरण संबंधी ज्ञापन दिये गये एवं समर्थन में विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत किये।

* **लिखे गये पत्र** - शिक्षकों की सामूहिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संगठन द्वारा लगातार राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा एवं आयुक्त कॉलेज शिक्षा सहित संबंधित अधिकारियों को लगातार विस्तृत पत्र लिख कर समाधान का प्रयास किया गया। कुछ प्रमुख समस्याओं का समाधान हो चुका है कुछ समस्याओं के समाधान का प्रयास चल रहे हैं। इस क्रम में संगठन द्वारा पीएच.डी. के दोहरे लाभ प्रकरण का निस्तारण करने, पूर्व सेवा लाभ सभी पात्र शिक्षकों के देने, निदेशक (अकादमी) पद पर शिक्षक की नियुक्ति करने, संतोषजनक ए.सी.आर. के आधार पर चयनित वेतनमान देने, आर.वी.आर.ई.एस. शिक्षकों को सी.ए.एस. लाभ देने, 30 जून 2013 के बाद के वरिष्ठ चयनित वेतनमान एवं पे-बैंड-4 के लिए शीघ्र स्क्रीनिंग करवाने, आर.वी.आर.ई.एस. में नियुक्त शिक्षकों को उनकी अनुदानित पद पर सेवा अवधि के छठे वेतनमान के एरियर हेतु अनुदान देने, पूर्व संचित उपार्जित अवकाश नकदीकरण हेतु अनुदान उपलब्ध करवाने अथवा उपार्जित अवकाश एवं मेडिकल अवकाश को राज्य सेवा में अग्रनीत करने, परिवीक्षा काल में कार्यरत शिक्षकों को राजकीय सेवा के सम्पूर्ण लाभ देने, सेवारत शिक्षकों को पीएच.डी. कोर्स वर्क से छूट देने, 2-1-2006 से 30-6-2006 के मध्य वार्षिक वेतनवृद्धि वाले शिक्षकों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने, संविदा शिक्षकों को यू.जी.सी. द्वारा अनुशंसित न्यूनतम वेतन देने, निजी पालिटेक्निक महाविद्यालयों के परीक्षा केन्द्र राजकीय महाविद्यालयों से हटाने, छात्र संघ चुनाव के दौरान झुंझुंनु महिला महाविद्यालय के शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करने वाली उपखण्ड अधिकारी पर कार्यवाही करने, भरतपुर के राजकीय महाविद्यालय से अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों का परीक्षा केन्द्र हटाने, नवगठित कृषि विश्वविद्यालयों में कुलपति पद नियुक्ति हेतु योग्यता संशोधन करने, आर.पी.एस.सी. द्वारा कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा हेतु शैक्षिक योग्यता पर पुन:विचार करने, 1-4-1994 के बाद नियुक्त शिक्षकों के स्थायी करने के आदेश प्रसारित करने, 1-4-1994 के बाद की वरिष्ठता सूची जारी करने, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें अन्य कर्मचारियों के साथ ही लागू करने, स्वायत्तशासी महाविद्यालय योजना हेतु शिक्षकों व विद्यार्थियों से विचार विमर्श करने, प्रतिनियुक्ति पर लगाये शिक्षकों को नियमानुसार टी.ए., डी.ए. एवं अवकाश स्वीकृत करने, आर.वी.आर.ई.एस. 2010 में राज्य सेवा का विकल्प नहीं देने वाले शिक्षकों के पद पर अनुदान जारी करने आदि विषयों पर राज्यपाल, मुख्यमंत्रीजी, उच्च शिक्षा मंत्री जी एवं सक्षम अधिकारियों से पत्र व्यवहार किया। संगठन ने माननीय संसाधन विकास मंत्रीजी को पत्र लिख कर आग्रह किया है कि कतिपय कारणों से कुछ शिक्षक समय पर रिफ्रेशर/ऑरियन्टेशन कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाए हैं अत: व्यापक हित में रिफ्रेशर/ऑरियन्टेशन कार्यक्रम की छूट 31 दिसम्बर 2015 तक बढ़ाई जाए।

गत सम्मेलन के पश्चात् प्राध्यापकों की समस्याओं के निराकरण हेतु संगठन विभिन्न गतिविधियों, भेंटवार्ताओं, ज्ञापनों एवं पत्राचार के माध्यम से निरन्तर सक्रिय रहा है। संगठन की सक्रियता के परिणामस्वरूप पूर्व में लंबित एवं तात्कालिक रूप से उत्पन्न कई समस्याओं का समाधान भी शिक्षक हित में हुआ है। किन्तु रुक्टा (राष्ट्रीय) कतिपय कुछ समस्याओं के समाधान से संतुष्ट होने वाला नहीं है, संगठन निरन्तर संघर्ष कर बढ़ते जाने के मंत्र पर चलने वाला है। अभी कई प्रमुख समस्याओं का समाधान बाकी है। इनका जब तक शिक्षक हित में समाधान नहीं हो जाता, हम रुकने, थकने या बैठने वाले नहीं है। लोकतंत्रात्मक पद्धति से आप सभी शिक्षक साथियों के सहयोग से शेष सभी समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयास जारी है।

सांगठनिक एवं वैचारिक गतिविधियाँ

* **प्रदेश अधिवेशन** - संगठन का 53 वाँ प्रांतीय अधिवेशन 18 व 19 फरवरी 2015 को गोविन्द गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में सम्पन्न हुआ। अधिवेशन में राज्य भर के लगभग 1500 शिक्षक साथियों ने हिस्सा लिया। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि अ. भा. रा. शैक्षिक महासंघ के महामंत्री प्रो. जे. पी. सिंघल एवं अध्यक्ष शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल रहे। कार्यक्रम में भारतीय गुरु शिष्य परंपरा पर केन्द्रित स्मारिका ''तेजस्विनावधीतमस्तु'' का भी विमोचन किया गया। देराश्री स्मृति व्याख्यान पेसिफिक विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति प्रो. भगवती प्रसाद शर्मा ने दिया। अधिवेशन में समूहशः बैठकों एवं खुले सत्र में विभिन्न शिक्षक समस्याओं पर मंथन किया गया। वार्षिक साधारण सभा में महामंत्री प्रतिवेदन एवं 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अंकेक्षित आय-व्यय विवरण तथा बेलेंसशीट को सदन ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। इसके अतिरिक्त साधारण सभा ने पूर्व में पारित प्रस्तावों की पुनः पुष्टि करते हुए दो नवीन प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए (1) शैक्षिक परिसरों के वातावरण को संस्कारक्षम बनाने के लिए सभी पक्षों द्वारा मिलजुल कर प्रयास किये जाये। (2) शोध हेतु सभी प्रकार के प्रोत्साहन एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। अधिवेशन के द्वितीय सत्र में ''मूल्य परक शिक्षा की प्रासंगिकता'' विषय पर आयोजित शैक्षिक संगोष्ठी के मुख्यवक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र कार्यवाह श्री हनुमानसिंह राठौड़ थे। समारोप कार्यक्रम रा. स्व. संघ के अखिल भारतीय सहसम्पर्क प्रमुख प्रो. अनिरुद्ध देशपांडे के मुख्य आतिथ्य एवं म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के कुलपति प्रो. कैलाश सोडानी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। अधिवेशन में अगल दो वर्ष के लिए नवीन कार्यकारिणी हेतु मनोनीत कार्यकर्ताओं के नामों की घोषणा भी की गई।
* **नवसंवत्सर कार्यक्रम** - केन्द्र के आह्वान पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रुक्टा (राष्ट्रीय) की विभिन्न इकाइयों ने भारतीय नववर्ष विक्रम संवत् २०७२ समारोह पूर्वक मनाया। शिक्षक समुदाय द्वारा व्यक्तिशः मित्रों एवं संबंधियों को बधाई संदेश एवं शुभकामनाएं प्रेषित की गईं। सामूहिक रूप से महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर में तथा चौराहों पर सभी को तिलक लगाकर एवं प्रसाद वितरित कर शुभकामनाएं दी गई। इसके अतिरिक्त अजमेर, गंगापुरसिटी, चुरू, सिरोही, नसीराबाद, तारानगर में भारतीय नववर्ष के महत्व एवं भारतीय कालगणना की वैज्ञानिकता पर संगोष्ठियाँ भी आयोजित की गई।
* **अम्बेड़कर जयंती पर नमन** - संगठन की विभिन्न इकाईयों द्वारा बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेड़कर जयंती पर उनके कर्त्तत्व एवं व्यक्तित्व का स्मरण करते हुए उनके बताए समरसता की राह पर चलने का संकल्प लिया गया।
* **गुरु वंदन कार्यक्रम** - केन्द्र की योजना के अनुरूप रुक्टा (रा.) की 128 इकाईयों द्वारा प्रदेश भर में गुरु-वंदन कार्यक्रम सम्पन्न किये गये। इस अवसर पर आदिगुरु महर्षि वेदव्यास को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए भारत की गुरु-शिष्य परम्परा, उनके बीच पावन संबंध और वर्तमान में उनकी भूमिका पर प्रेरक व्याख्यान आयोजित किए गए। प्रबुद्ध एवं चिंतनशील शिक्षकों/वक्ताओं द्वारा आदि गुरुओं के प्रेरणास्पद आचरण एवं त्याग के उदाहरणों से प्रेरित होकर बेहतर समाज निर्माण की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता जताई गई।
* **शिक्षक सम्मान निधि** - अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा प्रतिवर्ष अद्वितीय एवं अविस्मरणीय योगदान देने वाले शिक्षकों के सम्मान के निमित्त स्थापित अक्षय कोष हेतु संगठन की योजना से प्रदेश के 4400 से अधिक शिक्षक साथियों से रु. 100/- प्रति शिक्षक की सहयोग राशि प्राप्त हुई।
* **विभागीय सम्मेलन** - प्रदेश की योजना के अनुसार सितम्बर-अक्टूबर माह में रुक्टा (राष्ट्रीय) के 10 विभागों अलवर, भरतपुर, जयपुर-प्रथम, जयपुर-द्वितीय, जोधपुर, पाली, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा एवं कोटा विभागों के विभाग सम्मेलन सफलता पूर्वक सम्पन्न हुए। संगठन के अध्यक्ष, महामंत्री, संगठनमंत्री, उपाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री,

संभाग संगठन मंत्रियों की अलग-अलग विभागीय सम्मेलनों में संगठन के प्रान्तीय प्रतिनिधि के रूप में सहभागिता रही। इन विभागीय सम्मलेनों में प्रान्तीय प्रतिनिधियों द्वारा संगठन की गतिविधियों एवं विभागीय सम्मेलनों के औचित्य बताने सहित वैचारिक विषय रखे गये। सहभागियों द्वारा खुले सत्र में शिक्षक समस्याओं से अवगत कराया गया, उपस्थित प्रान्तीय प्रतिनिधि ने विभिन्न समस्याओं पर संगठन द्वारा की जा रही कार्यवाही से सदन को अवगत कराया गया, शेष रही नवीन समस्याओं की जानकारी प्रतिनिधियों द्वारा केन्द्र तक पहुँचाई गई।

* **राष्ट्रीय अधिवेशन में सहभागिता** - अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का त्रिदिवसीय छठा राष्ट्रीय अधिवेशन 9 से 11 अक्टूबर 2015 तक नागपुर में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में संगठन के 62 कार्यकर्ताओं ने सक्रिय सहभाग किया।
* **प्रदेश कार्यकारिणी बैठकें सम्पन्न** - 21 मार्च एवं 22 नवम्बर को संगठन की प्रांतीय कार्यकारिणी तथा 17 जून एवं 16 अगस्त को विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक सम्पन्न हुई। इनमें संगठन की विभिन्न गतिविधियों एवं आगामी कार्ययोजना पर गंभीरता से विचार विमर्श कर निर्णय लिए गए।
* **सदस्यता** - पिछले तीन वर्षों से संगठन की सदस्यता सीमित समय में करने की योजना पर कार्य हुआ है। पिछले वर्षों में रहे उत्साहजनक परिणाम के आलोक में इस वर्ष प्रदेश कार्यकारिणी ने संगठन की सदस्यता 1 से 15 जुलाई के मध्य ही एकत्र करने का निर्णय किया। सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से सार्थक परिणाम प्राप्त हुए एवं इस सत्र् हेतु राजकीय महाविद्यालयों से 4209, विश्वविद्यालयों से 204, एवं निजी संस्थाओं से 843 शिक्षकों की कुल **5256** सदस्यता प्राप्त हुई है। जो की गत वर्ष की सदस्यता से 231 अधिक रही। यह उल्लेखनीय है कि नए सत्र के प्रथम दिन अधिकतम सदस्यता दिवस पर सभी कार्यकर्त्ताओं के सक्रिय योगदान से एक ही दिन में रिकार्ड 4241 सदस्यता का संग्रहण हुआा।
* **राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक** - अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 14 जून 2015 को नई दिल्ली में एवं 8 अक्टूबर 2015 को नागपुर में महासंघ अध्यक्ष डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। संगठन की ओर से इन बैठकों में अध्यक्ष, महामंत्री एवं प्रदेश महिला प्रतिनिधि ने सक्रिय सहभाग किया।
* **इकाईयों द्वारा सम्पन्न विशेष कार्यक्रम** - राजकीय महाविद्यालय अजमेर इकाई द्वारा पृथ्वीराज जयंती, महाराणा प्रताप जयंती, अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस, सफाई अभियान एवं वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद इकाई द्वारा रक्षा बंधन पर्व, राजकीय कन्या महाविद्यालय अलवर इकाई एवं राजकीय महाविद्यालय टोंक इकाई द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न किए गए।

शिक्षक समस्याओं के समाधान हेतु तथा संगठन के कार्य एवं विचार के विस्तार हेतु हुई गतिविधियाँ योजनानुसार सफलता पूर्वक सम्पन्न हो सकी हैं तो इसका सम्पूर्ण श्रेय संगठन के सक्रिय कार्यकर्ताओं और आप सब शिक्षक बंधु, बहिनों को ही है। संगठन के प्रति आप सबके प्रेम, सहयोग एवं विश्वास के कारण ही यह संभव हो पाया है। इन गतिविधियों या समस्या-समाधान की प्रक्रिया में आपकी अपेक्षानुसार जो कार्य नहीं हुआ है तो उसके लिए पूर्णतः स्वयं को उत्तरदायी मानकर आपसे करबद्ध क्षमायाचना करता हूँ तथा आपके निरन्तर सहयोग, मार्गदर्शन एवं विश्वास हेतु हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

भवदीय

(डॉ. नारायणलाल गुप्ता)
[महामंत्री]